RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 28 FEBRUARY TO 05 MARCH 2024 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 23 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

भारत आ रहे तीन रूसी टैंकरों पर अमेरिका का बैन, कैसे पहुंचेगा तेल? Page 2

शेयर बाजार में भारी गिरावट सेंसेक्स 600 अंक टूटा Page 3

यूरोप की तरह BRICS में एक करेंसी! Page 4

editoria!

सवाल बराबरी का

एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने देश के सुरक्षा ढांचे के अंदर पलती पितृसत्तात्मक सोच पर कड़ी चोट की है। इस बार मामला कोस्टगार्ड से जुड़ा है। हालांकि अभी फैसला नहीं आया है, मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रुख ने इतना तय कर दिया है कि कोस्टगार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमिशन देने में अब और टालमटोल नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में अचरज की बात यही है कि महिला-पुरुष बराबरी को लेकर देश-दुनिया में चल रहे विमर्श से हमारे सरकारी ढांचे का कोई हिस्सा इस कदर उदासीन कैसे हो सकता है। ध्यान रहे कि सशस्त्र बलों में बराबरी का व्यवहार पाने का महिलाओं का संघर्ष भी इसी दौर में चला। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के फैसले में आर्मी को निर्देश दिया कि महिलाओं को परमानेंट कमिशन देना होगा। अदालत ने इसके खिलाफ दी जाने वाली सारी दलीलों को खारिज कर दिया। बावजूद इसके, कोस्टगार्ड से जुड़े इस मामले में भी मिलते-जुलते से तर्क सुनने को मिले। मिसाल के तौर पर, कहा गया कि कोस्टगार्ड की फंक्शनिंग सेना या नौसेना से अलग है। ठीक ही अदालत ने इस तरह की दलीलों के विस्तार में गए बगैर ही उन्हें यह कहते हुए काट दिया कि 2024 में फंक्शनल डिफरेंस वाले तर्क नहीं चलेंगे। चाहे जो भी डिफरेंस हो और जो भी बाधाएं हों, महिलाओं को परमानेंट कमिशन देना ही होगा। जाहिर है, अब आगे बात इस पर नहीं होगी कि यह देना है या नहीं, मसला सिर्फ यह होगा कि कैसे देना है। सवाल यह भी है कि जब सशस्त्र बलों में यह मामला उठा था, तब भी कहा गया था सरकार को जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी बनाने की पहल करनी चाहिए। मगर ऐसा लगता है कि सरकार की ओर से इस दिशा में कोई खास सार्थक प्रयास नहीं हुए। वरना सर्वोच्च अदालत के सामने 'फंक्शनल डिफिकल्टीज' गिनाने की कवायद में लगने के बजाय यह बताया जाता कि उन बाधाओं को दूर करने में कितनी कामयाबी मिली है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि यह मामला याचिकाकर्ता तक सीमित नहीं है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर इस खास मामले का जिक्र करें तो भी इंडियन कोस्टगार्ड में पायलट के तौर पर 14 साल के अपने कार्यकाल के दौरान याचिकाकर्ता ने समंदर में 300 जानें बचाईं। उनके खाते में 4500 फ्लाइंग आवर्स दर्ज हैं जो सशस्त्र बलों में महिला और पुरुष दोनों श्रेणियों में सबसे ज्यादा है।

गांवों-शहरों में गैप घटा, कुल खर्च में खाने-पीने का हिस्सा कम हुआ

नई दिल्ली। एजेंसी

पिछले 11 वर्षों में खाने-पीने से लेकर तमाम तरह की चीजों और सेवाओं पर प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च ढाई गुना तक बढ़ गया है। इस दौरान जहां कुल खर्च में खाने-पीने की चीजों की हिस्सेदारी घटी है, वहीं यात्रा और दूसरी चीजों पर खर्च बढ़ा है। साथ ही, ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच खर्च में अंतर घट गया है। यह जानकारी सरकार के लेटेस्ट हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से मिली। जानिए पूरी डिटेल...

रूरल-अर्बन गैप कितना घटा है

ताजा सर्वे के मुताबिक, 2022-23 में ग्रामीण इलाकों में ऐवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (श्र्ण्) 3773 रुपये और शहरी इलाकों में 6459 रुपये रहा। 2010-11 में ये आंकड़े 1430 रुपये और 2630 रुपये पर थे। इस तरह रूरल एरिया में खर्च 2.6 गुना और अर्बन एरिया में 2.5 गुना बढ़ गया। इसके साथ ही रूरल-अर्बन गैप घटा है। 2010-11 में शहरों में औसत MPCE गांवों में खर्च से 84% अधिक था। 2022-23 में फासला घटा और यह करीब 71% ही अधिक रह गया है।

क्या बदल रहा खान-पान का पैटर्न

2011-12 में ग्रामीण इलाकों में कुल मासिक खर्च में खाने-पीने की हिस्सेदारी 52.9% थी। 2022-23

में यह 46.4% पर आ गई। शहरों में भी आंकड़ा 42.6% से घटकर 39.2% पर आ गया। गांवों में खाने-पीने पर प्रति व्यक्ति एक महीने का खर्च 1750 रुपये और शहरों में 2530 रुपये रहा। फूड आइटम्स में सबसे ज्यादा खर्च बेवरेजेज और बाहर से खरीदे गए कुक्ड आइटम्स का दिख रहा है।

खाने से अलग चीजों पर खर्च कितना

खाने-पीने से अलग की चीजों पर गांवों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च 2023 रुपये रहा। कुल खर्च में इसकी हिस्सेदारी 54% रही। शहरों में नॉन-फूड आइटम्स पर MPCE 3929 रुपये रहा। कुल खर्च में इसका हिस्सा 61% रहा।

टॉप और बॉटम में कितना अंतर?

प्रति व्यक्ति मासिक खर्च के हिसाब से गांवों में जो सबसे निचले 5ज्ञ लोग हैं, वे 1373 रुपये महीने में गुजारा करते पाए गए। शहरों में इस तबके के लिए ऐवरेज MPCE 2001 रुपये रहा। सबसे ऊपर के 5% लोगों के लिए गांवों में ऐवरेज MPCE 10501 रुपये रहा। उनके जैसे ही शहरी लोगों का प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च 20824 रुपये रहा।

राज्यवार क्या है हाल

सबसे ज्यादा श्र्ण् सिक्किम में रहा। वहां ग्रामीण इलाकों के लिए यह 7731 रुपये और शहरी इलाकों में 12105 रुपये रहा। सबसे कम आंकड़ा छत्तीसगढ़ में 2466 रुपये और 4483 रुपये का रहा। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग खर्च 6576 रुपये और शहरी इलाकों में 8217 रुपये रहा। यूपी में आंकड़ा 3191 रुपये और 5040 रुपये है। बिहार के रूरल एरिया में 3384 रुपये और अर्बन एरिया में 4768 रुपये का आंकड़ा है। महाराष्ट्र के गांवों में श्र्ण् 4010 रुपये और शहरों में 6657 रुपये है।

अलग-अलग सोशल ग्रुप्स की तस्वीर कैसी है?

2022-23 के सर्वे के मुताबिक, रूरल एरिया में एऊ के लिए ऐवरेज श्र्ण् 3016 रुपये और शहरी इलाकों में 5414 रुपये है। एण के लिए गुजर-बसर पर प्रति व्यक्ति मासिक खर्च का आंकड़ा गांवों में 3474 रुपये और 5307 रुपये का है। ध्ँ के लिए यह 3848 रुपये और 6177 रुपये है। इनके अलावा बाकी लोगों के लिए गांवों में औसत श्र्ण् 4392 रुपये और शहरों में 7333 रुपये है।

टोल कलेक्शन ने तोड़े सारे रेकॉर्ड 50 हजार करोड़ रुपये के हुआ पार

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल कलेक्शन में बंपर उछाल आया है। इस वित्त वर्ष में जनवरी के अंत तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल कलेक्शन 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। इस साल टोल कलेक्शन के 62,000 करोड़ रुपये के रेकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। टोल कलेक्शन में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कलेक्शन में इस तेजी की वजह टोल वाली सड़कों का विस्तार और ईंएर्ऊ यूजर्स की संख्या बढ़ना है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस वित्त वर्ष के पहले दस महीनों में टोल वाली सड़कों में उल्लेखनीय वृद्धि और नई सड़कों को जोड़ने के कारण देश का टोल कलेक्शन 53,289.41 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

इतना बढ़ा टोल कलेक्शन

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से जनवरी तक औसत मासिक टोल कलेक्शन 5,328.9 करोड़ रुपये था। यह दर्शाता है कि वित्त वर्ष 2024 में टोल संग्रह 62,000 करोड़ रुपये के रेकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की राह पर है। इस वित्त वर्ष के नवंबर के अंत तक देश में टोल वाली सड़कों की कुल लंबाई 75 फीसदी बढ़कर 25,996 किमी से 45,428 किमी हो गई है।

और होगा इजाफा

सरकार जल्द ही जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम की शुरुआत करने जा रही है। इससे टोल कलेक्शन में और इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है। जानकारों का मानना है कि जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली सरकारी राजस्व को बढ़ावा देगी। यह ड्राइवरों को वैकल्पिक रास्तों की बजाय मार्गों के बजाय टोल सड़कों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। हालांकि, उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि इससे टोल सड़कों पर ट्रैफ़िक बढ़ सकता है और सरकार के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। पिछले साल नवंबर के अंत तक 79.8 मिलियन से ज्यादा FASTag जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर FASTag के जरिए हर दिन का औसत टोल कलेक्शन करीब 147.31 करोड़ रुपये है।

भारत आ रहे तीन रूसी टैंकरों पर अमेरिका का बैन, कैसे पहुंचेगा तेल?

नई दिल्ली। एजेंसी

अमेरिका ने शुक्रवार को 14 रूसी तेल टैंकरों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था, क्योंकि वे पश्चिम देशों की ओर से लगाए गए प्राइस कैप से ज्यादा कीमत पर तेल निर्यात कर रहे थे। इसके बावजूद ब्लैक लिस्ट में शामिल तीन टैंकर तेल लेकर भारत आ रहे हैं। फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत रूस से भारी मात्रा में रियायती कीमतों पर तेल खरीद रहा है. अगले कुछ सप्ताह में भी तेल लदे रूसी टैंकर भारत पहुंचने वाले हैं। लेकिन उन तीन टैंकरों की चर्चा हो रही है जिसे अमेरिका ने बैन कर दिया है. इसके बावजूद तीनों टैंकर तेल लेकर भारत आ रहे हैं।

अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगले कुछ सप्ताह के दौरान भारतीय रिफाइन कंपनियों को कच्चा तेल पहुंचाने वाले टैंकर में कम से कम तीन टैंकर ऐसे हैं जिसे हाल ही में अमेरिका ने बैन किया है। अमेरिका ने शुक्रवार को 14 रूसी तेल टैंकरों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, क्योंकि वे पश्चिम देशों की ओर से लगाए गए प्राइस कैप से ज्यादा कीमत पर तेल निर्यात कर रहे थे। पश्चिमी देशों की ओर से रूसी तेल की प्राइस कैप 60 डॉलर प्रति बैरल है।

किसी बड़ी समस्या की आशंका नहीं: सूत्र

जहाज ट्रैकिंग डेटा से अनुसार, भारत आ रहे तीन टैंकरों में से एक जॉर्जी मैस्लोव इस सप्ताह के अंत में सिक्का बंदरगाह पहुंचेगा। वहीं, एक अन्य टैंकर अनातोली कोलोडकिन भी अप्रैल में सिक्का बंदरगाह पर पहुंचेगा। इस महीने की शुरुआत में अनातोली कोलोडकिन टैंकर ने वाडिनार बंदरगाह पर कच्चे तेल की डिलीवरी की थी। ब्लैक लिस्ट में शामिल एक और टैंकर एनएस कैप्टन भी मार्च और अप्रैल में वाडिनार बंदरगाह पर तेल लेकर पहुंचेगा।

हालांकि, उद्योग से जुड़े अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि ब्लैक लिस्टेड टैंकर से डिलीवरी से किसी बड़ी समस्या की कोई आशंका नहीं है। क्योंकि अमेरिका ने ब्लैक लिस्टेड टैंकर को 45 दिनों तक तेल निर्यात करने की अनुमति दी है।

45 दिनों के बाद ब्लैक लिस्टेड टैंकर से डिलीवरी नहीं

अमेरिका समेत जी-7 के अन्य देशों ने मिलकर दिसंबर 2022 में रूसी तेल की कीमत कैप लगाने की घोषणा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, रूस एक महीने में भारत को चार दर्जन कार्गो की डिलीवरी करता है। सूत्रों के अनुसार, ब्लैक लिस्टेड टैंकर के 45 दिन हो जाने के बाद भारतीय रिफाइन कंपनियां इन टैंकरों की मदद से तेल नहीं आयात करेंगी। सूत्रों के मुताबिक, सरकार नहीं चाहती है कि भारतीय रिफाइन कंपनियां खुलेआम जी-7 के प्राइस कैप का उल्लंघन करें। ऐसे में प्रतिबंधों से बचने के लिए कंपनियां स्वीकृत यानी बिना प्रतिबंधित टैंकर से ही डिलीवरी ले। पिछले कुछ महीनों के दौरान भारत आने वाले रूसी टैंकरों द्वारा प्राइस कैप का उल्लंघन के मामले सामने आए हैं. जिसके कारण भारतीय रिफाइन कंपनियों ने कार्गो को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

IOC, GAIL और ONGC समेत छह सरकारी कंपनियों पर लगातार तीसरी तिमाही में लगा जुर्माना

नई दिल्ली। एजेंसी

तीन सरकारी कंपनियों आईओसी (IOC), ओएनजीसी (ONGC) और गेल (इंडिया) समेत छह सरकारी कंपनियों पर लगातार तीसरी तिमाही लगा है। इन कंपनियों पर बोर्ड में डायरेक्टर्स की अनिवार्य संख्या रखने का नियम पूरा नहीं करने के कारण लगातार तीसरी तिमाही में जुर्माना लगाया गया है। शेयर बाजार पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तेल रिफाइनिंग और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों आईओसी, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड (Oil India Ltd), गैस कंपनी गेल (GAIL) और तेल रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) एवं मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) पर कुल 32.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सभी कंपनियों ने शेयर बाजार पर अलग-अलग दी सूचना में 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही में स्वतंत्र निदेशकों या अनिवार्य महिला निदेशक की अपेक्षित संख्या नहीं होने के कारण बीएसई और एनएसई द्वारा लगाए गए जुर्माने का विवरण दिया। कंपनियों ने हालांकि बताया कि निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जानी है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। पिछली दो तिमाहियों में भी कंपनियों को इसी कारण से जुर्माने का सामना करना पड़ा था।

हर कंपनी पर कितना है जुर्माना

सार्वजनिक क्षेत्र की छह कंपनियों ने शेयर बाजार को अलग-अलग दी सूचना में कहा कि उन पर तीसरी तिमाही के लिए प्रत्येक पर 5,42,800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ओएनजीसी, एचपीसीएल, एमआरपीएल, गेल और ओआईएल को अपने बोर्ड में जरूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं होने के लिए जुर्माना का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर आईओसी को अपने निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं रखने के लिए जुर्माना का सामना करना पड़ा। मानदंडों के अनुसार कंपनियों को कार्यकारी या कार्यात्मक निदेशकों के समान अनुपात में स्वतंत्र निदेशक रखने होते हैं। निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक का होना भी जरूरी है।

क्या है कॉलर नेम प्रेजेंटेशन

जिसकी TRAI ने की सिफारिश, मिलेगी ट्रूकॉलर जैसी सुविधा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अब आने वाले समय में आपको अनचाही कॉल (Spam Calls) से छुटकारा मिलने वाला है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने कॉलर नेम प्रेजेंटेशन (CNP) की सिफारिश की है। इसमें आपको ट्रूकॉलर जैसी सुविधा मिलेगी। इस सर्विस के शुरू होने पर ग्राहक अपने फोन की स्क्रीन पर कॉलर का नाम देख सकेंगे। ट्राई ने कहा है कि सरकार को एक तय तारीख के बाद भारत में बेचे जाने वाले सभी फोन में सीएनएपी यानी कॉलर नेम प्रेजेंटेशन की सुविधा देने के लिए दूरसंचार कंपनियों को उपयुक्त निर्देश जारी करना चाहिए। मोबाइल फोन का कनेक्शन लेते समय भरे जाने वाले ग्राहक आवेदन पत्र (CAF) में दिए गए नाम और पहचान जानकारी का इस्तेमाल सीएनएपी सर्विस के दौरान किया जा सकता है।

अनचाही कॉल्स से मिलेगी राहत

अभी देश में ट्रूकॉलर, स्मार्टफोन टूल और भारत कॉलर जैसे ऐप कॉल करने वाले शख्स की पहचान की सुविधा देते हैं। लेकिन ये सर्विस लोगों से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित है। यह हमेशा विश्वसनीय नहीं होती है। लेकिन कॉलर नेम प्रेजेंटेशन से लोगों को अनचाही कॉल्स से छुटकारा पाने में काफी मदद मिलेगी।

ऐसे मिलेगी सुविधा

यह सुविधा ग्राहक के अनुरोध पर ही सभी दूरसंचार कंपनियां मुहैया कराएंगी। अभी तक मोबाइल पर कॉल करने वाले शख्स का नाम लिखकर नहीं आता है। अभी सिर्फ नंबर दिखाई देता है। लेकिन कॉलर नेम प्रेजेंटेशन की सुविधा के बाद कॉल करने वाले हर शख्स का नाम लोगों के मोबाइल पर दिखाई देगा। ऐसे में लोगों को अनचाही कॉल्स से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। सीएनएपी सुविधा शुरू होने के बाद ग्राहक अपने फोन की स्क्रीन पर कॉलर का नाम देख सकेंगे। दूरसंचार नियामक ने सुझाव दिया कि सभी एक्सेस सेवा प्रदाता अपने टेलीफोन ग्राहकों को उनके अनुरोध पर सीएनएपी सेवा मुहैया कराएं। ट्राई ने नवंबर, 2022 में इस संबंध में एक परामर्श पत्र जारी कर हितधारकों, जनता और उद्योग की टिप्पणियां मांगी थीं।

दुनिया के इस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा बिलिनेयर

टॉप 10 में दिल्ली-मुंबई भी शामिल

नई दिल्ली। एजेंसी

दुनिया के टॉप 10 रईसों में से नौ अमेरिका के हैं। इनमें एकमात्र नॉन-अमेरिकन रईस फ्रांस के बर्नार्ड आरनॉल्ट हैं। इस लिस्ट में वह 197 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर हैं। पहले दो नंबर पर एलन मस्क (208 अरब डॉलर) और दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस (198 अरब डॉलर) हैं। इसके अलावा मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव बालमर, वॉरेन बफे, लैरी पेज, लैरी एलिसन और सर्गेई ब्रिन टॉप 10 में शामिल हैं। ये सभी अमेरिका के हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किस शहर में सबसे ज्यादा बिलिनेयर रहते हैं? इसका उत्तर है न्यूयॉर्क। अमेरिका के इस शहर में 101 ऐसे रईस रहते हैं जिनकी नेटवर्थ एक अरब डॉलर यानी 8,288 करोड़ रुपये से अधिक है।

न्यूयॉर्क के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बिलिनेयर हॉन्ग कॉन्ग में रहते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक यह शहर 70 बिलिनेयर्स का घर है। इसके बाद चीन के दो शहर बीजिंग और शंघाई का नंबर है। बीजिंग में 68 बिलिनेयर्स रहते हैं जबकि शंघाई 65 बिलिनेयर्स का ठिकाना है। चीन के सबसे बड़े रईस झोंग शैनशैन हैं। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 66.4 अरब डॉलर है और वह

दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 22वें नंबर पर हैं। इस लिस्ट में अगले नंबर पर यूके की राजधानी लंदन है। इस शहर में 63 बिलिनेयर रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोपीचंद हिंदूजा ब्रिटेन के सबसे अमीर शख्स हैं। उनके परिवार की नेटवर्थ 35 अरब पाउंड है।

दिल्ली-मुंबई

रूस की राजधानी मॉस्को इस लिस्ट में छठे नंबर पर है। इस शहर में 61 बिलिनेयर रहते हैं। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक व्लादिमिर पोतानिन रूस के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी नेटवर्थ 30.4 अरब डॉलर है और वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 50वें नंबर पर हैं। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में 56 बिलिनेयर रहते हैं। इनमें एशिया और भारत के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी भी शामिल हैं। अंबानी 114 अरब की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 11वें नंबर पर हैं। चीन के शेनजेन में 54, सिंगापुर में 46, दिल्ली में 37 और सैन फ्रांसिस्को में 37 बिलिनेयर रहते हैं।

शेयर बाजार में भारी गिरावट

सेंसेक्स 600 अंक टूटा

लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 6.24 लाख करोड़ रुपये घटा

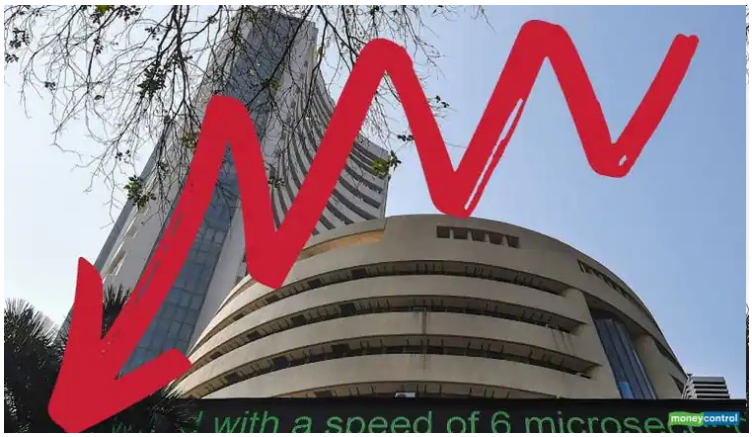

मुंबई। एजेंसी

चौतरफा बिकवाली के बीच शेयर बाजार 28 फरवरी को भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स जहां 790 अंक टूट गया। वहीं निफ्टी इंडेक्स गिरकर 22,000 के नीचे आ गया। इसके चलते दिन भर में आज निवेशकों के करीब 6.24 लाख करोड़ रुपये डूब गए। बीएसई के सभी सेक्टरोल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सबसे अधिक गिरावट ऑयल एंड गैस, पावर, रियल्टी, यूटिलिटी, ऑटो और टेलीकम्यनिकेशंस शेयरों में देखने को मिला। यहां तकि छोटे और मझोले शेयरों में भी जबरदस्त मुनाफावसूली रही। कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 790.34 अंक या 1.08% की गिरावट के साथ 72,304.88 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 247.20 अंक या 1.11% फीसदी टूटकर 21,951.15 के स्तर पर बंद हुआ।

क्यों गिरा शेयर बाजार?

आज की गिरावट के पीछे मुख्य कारण इंडेक्स में भारी वेटेज रखने वाले शेयरों खासतौर से फाइनेंशियल शेयरों का कमजोर प्रदर्शन रहा। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI और ICICI बैंक 1 फीसदी से ज्यादा गिरकर बंद हुए। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2 फीसदी से ज्यादा टूटकर बंद हुआ। बाजार पर ग्लोबल बाजारों में कमजोरी का भी असर रहा, जो गुरुवार को पर्सनल एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी होने से पहले लाल निशान में रहे।

ब्रॉडर मार्केट में भी तेज गिरावट देखी गई। बीएसई के मिडकैप इंडेक्स और बीएसई का स्मॉलकैप इंडेक्स दोनों 2 फीसदी टूट गए। पिछले कुछ महीनों से ब्रॉडर मार्केट में ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर चिंताएं जताई जा रही थीं, जिसने निवेशकों को लगातार आंशिक मुनाफावसूली करने के लिए मजबूर किया है। इसके अलावा निवेशक अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों पर भी बारीकी से नजर रख रहे हैं क्योंकि इसी से यह संकेत मिल सकेगा कि फेडरल रिजर्व कब ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू करेगा।

निवेशकों के 6.24 लाख करोड़ डूबे

बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 28 फरवरी को घटकर 385.75 लाख करोड़ रुपये पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 27 फरवरी को 391.99 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 6.24 लाख करोड़ रुपये घटा है। या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की वेल्थ में करीब 6.24 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है।

अपोलो एंडुट्रैक्स रेंज है मजबूती की नई परिभाषा

अपोलो टायर्स की अनूठी पहल, नेट्रैक्स इंदौर में ले सकेंगे ड्राइव का अनुभव

पीथमपुर। आईपीटी नेटवर्क

देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है, और सरकार द्वारा साल-दर-साल बढ़ते खर्च के कारण इसे और भी अधिक बढ़ावा मिल रहा है। प्रमुख टायर निर्माता कंपनी अपोलो टायर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इस वृद्धि का लाभ उठाते हुए इंदौर में नेट्रैक्स फैसिलिटी में विशेष रूप से बनाए गए ट्रैक पर ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में विशेष रूप से अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए वाहन मालिकों, बिज़नस पार्टनर और मीडिया को ड्राइव का अनुभव प्रदान किया।

देश में कमर्शियल वाहन टायरों के लिए यह इस तरह का पहला ड्राइव अनुभव है। यह इंदौर के नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स (नेट्रैक्स) में आफ्टरमार्केट ग्राहकों और मीडिया के लिए आयोजित किया गया था। ड्राइव का उद्देश्य अपोलो एंडुट्रैक्स रेंज की मजबूती का प्रदर्शन करना था, जिसे ग्राहकों के सुझावों के साथ नए सिरे से विकसित किया गया है। विशेष रूप से तैयार ट्रैक में कीचड़/गड्ढे, गंदगी का ढलान, उबड़-खाबड़, पत्थर और बजरी शामिल थी, इसमें टायरों की अधिकतम टिकाऊपन, उच्च अपटाइम और ग्रिप का परीक्षण किया गया और प्रतिभागियों को एक रोमांचकारी अनुभव दिया।

कंपनी को गर्व है कि टिपर सेगमेंट में अग्रणी वाणिज्यिक वाहन ओईएम (OEM) के वे पसंदीदा पार्टनर है और समग्र आधार पर भी इस सेगमेंट में उसकी बाजार हिस्सेदारी सबसे अधिक है। अपोलो टायर्स की एंडुट्रैक्स रेंज में एंडुट्रैक्स एमडी+, एंडुट्रैक्स एमडी और एंडुट्रैक्स एमए शामिल हैं। बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ऑफ-रोड और ऑन-रोड उपयोगों और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के खनन के लिए टिपर ट्रकों में इनका उपयोग किया जाता है।

अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डिजिटल वॉलेट से खरीद सकेंगे टिकट

RBI ने दी ये बड़ी राहत

नई दिल्ली। एजेंसी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वालों को बड़ी राहत दी। RBI ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) के मास्टर डायरेक्शन में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत बैंक और नॉन बैंक रिजर्व बैंक की अनुमति के बाद अलग-अलग तरीके के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) जारी कर सकते हैं। इन्हें खाते के बिना विभिन्न सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क पर भुगतान के लिए PPI जारी करने की अनुमति होगी। RBI के मुताबिक यात्रियों को डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा, बेहतर सुविधा, भुगतान में तेजी और किफायती सेवा प्रदान करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के भुगतान में सक्षम पीपीआई को जारी करने की मंजूरी दी गई है।

क्या होगा फायदा?

RBI द्वारा KYC के बिना PPIs जारी करने की मंजूरी की बाद मेट्रो, बस, ट्रेन, जलमार्ग, टोल और पार्किंग सेवाओं का भुगतान अब प्रीपेड वॉलेट और कार्ड के माध्यम से डिजिटल रूप से किया जा सकता है। देश में हर रोज बड़ी संख्या में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं। ऐसे में यह इंस्ट्रूमेंट्स यात्रियों को डिजिटल पेमेंट की सहूलियत देगा, जो किफायती होगा और उनका समय भी बचाएगा। यह सुविधा सुरक्षित होगी और उन्हें पेमेंट के लिए कैश के अलावा दूसरे ऑप्शन भी देगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक ये कदम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

क्या है PPI?

PPI ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें जमा किए गए पैसों की मदद से सामान या सेवाओं के लिए भुगतान या फिर पैसों का लेनदेन किया जा सकता है। इन पीपीआई में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या सीधे बैंक खाते की मदद से रकम को जमा किया जा सकता है।

कितने तरह के PPI हैं?

अभी देश में तीन तरह के PPI हैं- सेमी क्लोज्ड सिस्टम PPI, क्लोज्ड सिस्टम PPI और ओपन सिस्टम PPI। PPI का होल्डर वह व्यक्ति होता है जो PPI issuer से PPI प्राप्त करता/खरीदता है। हालांकि gift PPI के मामले में, कोई अन्य भी होल्डर हो सकता है।

यूरोप की तरह BRICS में एक करेंसी!

रूस की चाहत को चीन जैसे हाथी का साथ, पर क्यों पसोपेश में भारत?

नई दिल्ली। एजेंसी

BRICS में भारत दोराहे पर खड़ा है। उसे दो परस्पर विरोधी फैसलों के बीच चुनाव करना है। भारत को तय करना है कि उसे ब्रिक्स करेंसी के कॉन्सेप्ट को अपनाना है या इस विचार को लेकर अपना रुख ठंडा रखना है? BRICS उभरती अर्थव्यवस्थाओं का गठबंधन है। इसकी नींव 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने यूरोप और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए डाली थी। बाद में दक्षिण अफ्रीका भी इस गुट में शामिल हो गया था। अब सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शामिल होने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ है। हालांकि, ब्रिक्स सिर्फ व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहता है। खासतौर से रूस यूरो और डॉलर की तर्ज पर एक ग्लोबल करेंसी की वकालत कर रहा है। रूस का यह प्रस्ताव उन आर्थिक बंदिशों का नतीजा है, जिनका सामना उसने यूक्रेन के साथ युद्ध में किया है। इन प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। इससे रूस को वैकल्पिक रास्ते तलाशने पड़े।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए कॉमन करेंसी के पीछे का विचार अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देना है। 1944 से इसने दुनियाभर में रिजर्व करेंसी के तौर पर अपना दबदबा कायम करके रखा है। दुनिया में करीब 80% व्यापार अमेरिकी मुद्रा डॉलर में होता है। 60 फीसदी ग्लोबल रिजर्व डॉलर में है। इसके कारण अमेरिका को करीब-करीब हर चीज पर कंट्रोल करने का अधिकार मिल जाता है। कॉमन ब्रिक्स करेंसी बनाकर उभरती अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा संतुलित और न्यायसंगत ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की मंशा रखती हैं।

क्यों स्थानीय करेंसी का इस्तेमाल मुश्किल?

यहां तक तो बात समझ आती है। लेकिन, सवाल यह उठता है कि ब्रिक्स के देश अपनी-अपनी

स्थानीय करेंसी का इस्तेमाल करके व्यापार क्यों नहीं कर सकते। इसे समझने के लिए रूस और भारत का उदाहरण लेते हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण जब रूस पर प्रतिबंध लगे तो उसने भारतीय रुपये में लेनदेन के साथ रियायती मूल्य पर भारत को तेल बेचना शुरू कर दिया। हालांकि, यह व्यवस्था रूस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुई। कारण है कि उसके पास जो रुपया पहुंचा, उसका इस्तेमाल करने के लिए रास्ते खोजने में उसे कठिनाई हुई। अन्य देशों के साथ व्यापार के लिए सीमित गुंजाइश ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए स्थानीय करेंसी के इस्तेमाल की सीमाओं को दिखाया। इन परिस्थितियों को देखते हुए कॉमन ब्रिक्स करेंसी भारत के लिए ठीक हो सकती है। इसके संभावित फायदों को देखते हुए सरकार इस संभावना पर चर्चा करने के लिए तैयार भी दिख रही है। हालांकि, इस मामले में चीन की भूमिका को लेकर चिंताएं हैं। चीन कई साल से अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रभाव को सक्रिय रूप से चुनौती देता रहा है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं की स्थापना इसकी बानगी है।

चीन के लिए फायदेमंद होगी व्यवस्था

जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का तर्क है कि कॉमन करेंसी चीन के लिए फायदेमंद होगी। दूसरे संभावित जोखिमों को लेकर सावधान करते हैं। यूरोजोन का अनुभव दिखाता है कि अलग-अलग अर्थव्यवस्थाओं में सिंगल करेंसी का प्रबंधन जटिलताओं को जन्म दे सकता है। 2008 में ग्लोबल वित्तीय संकट के दौरान ग्रीस और पुर्तगाल जैसे देशों को भारी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। कारण है कि उनकी खास जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई मौद्रिक नीतियां जर्मनी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के हितों से टकरा गई थीं।

यही वो बातें हैं जो कॉमन ब्रिक्स करेंसी की राह में अनिश्चितता पैदा करती हैं। चीन का तो वैसे भी बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस विचार को अमलीजामा पहनाने के लिए ब्रिक्स सेंट्रल बैंक की जरूरत होगी। तमाम अर्थशास्त्रियों को लगता है कि यह विचार बेहद पेचीदा है। इस दिशा में कदम बढ़ा पाना तकरीबन नामुमकिन है। इसमें सबसे बड़ा फायदा चीन और रूस को होना है। पश्चिमी देशों की ये दोनों देश वैसे भी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। यही वजह है कि दोनों पुरजोर के साथ इसकी वकालत करने में लगे हैं।

इफको दुनिया की नं. 1 सहकारी संस्था

वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर (डबल्यू सी एम) 2023 की रिपोर्ट में फिर से शीर्ष पर

'सहकार से समृद्धि' के सपने को साकार करने की दिशा में वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन

नई दिल्ली। एजेंसी

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) को पुनः दुनिया की शीर्ष 300 सहकारिताओं में पहला स्थान मिला है। यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है। यह दर्शाता है कि इफको राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इंटरनेशनल कोआपरेटिव एलायंस (ICA) की 12वीं वार्षिक वर्ल्ड कोआपरेटिव मॉनीटर (WCM) रिपोर्ट के 2023 संस्करण के अनुसार यह देश के सकल घरेलु उत्पाद एवं आर्थिक विकास में इफको के कारोबारी योगदान को दर्शाता है। कुल कारोबार के मामले में इफको पिछले वित्तीय वर्ष के अपने 97वें स्थान के मुकाबले 72वें स्थान पर पहुंच गया है। अपनी 35,500 सदस्य सहकारी समितियों, 25,000 पैक्स और 52,400 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के साथ इफको 'आत्मनिर्भर भारत' और 'आत्मनिर्भर कृषि' की ओर अग्रसर सहकार से समृद्धि का सशक्त उदाहरण है।

इफको ने पिछले कई वर्षों से अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है जो इफको और इसके प्रबंधन के सहकारी सिद्धांतों में अटूट भरोसे का प्रमाण है। इसे देश में मजबूत सहकारी आंदोलन के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसे केंद्र द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन और श्री अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार के कुशल नेतृत्व से गति मिली है। मंत्रालय द्वारा की गई पहल से अनुकूल माहौल बना है और भारत में सहकारिता आंदोलन को फलने-फूलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री के ध्येय 'सहकार से समृद्धि' से प्रेरणा लेते हुए और विभिन्न फसलों पर वर्षों की कड़ी मेहनत, अनुसंधान और प्रयोग की बदौलत इफको ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया और नैनो डीएपी विकसित किया।

2000 रुपये के नोट वापस लेने के फैसले का हुआ असर

RBI ने दी बड़ी जानकारी

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2,000 के बैंक नोट को चलन से हटाने का प्रभाव दिखने लगा है। आंकड़ों के अनुसार, नौ फरवरी को समाप्त सप्ताह में चलन में मुद्रा की वृद्धि एक साल पहले के 8.2 प्रतिशत से घटकर 3.7 प्रतिशत रह गई है। बता दें कि चलन में मुद्रा (सीआईसी) से तात्पर्य प्रचलन में मौजूद नोटों और सिक्कों से है। वहीं जनता के पास मौजूद मुद्रा से तात्पर्य बैंकों के पास जमा नकदी को घटाकर प्रचलन में मौजूदा नोटों और सिक्कों से होता है। आरबीआई के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा में जनवरी में दो अंक में वृद्धि हुई है। इसकी वजह भी 2,000 के नोटों को हटाना है। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार, आरक्षित मुद्रा (आरएम) की वृद्धि नौ फरवरी, 2024 को घटकर 5.8 प्रतिशत रह गई, जो एक साल पहले 11.2 प्रतिशत थी। आरएम में सीआईसी के अलावा आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशि और केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमा शामिल हैं।

पिछले साल 2,000 के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा

नवंबर, 2016 में नोटबंदी की घोषणा के बाद 2,000 का नोट लाया गया था। केंद्रीय बैंक ने 19 मई, 2023 को 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी।

8,897 करोड़ रुपये मूल्य के नोट अब भी जनता के पास

31 जनवरी तक, 2,000 रुपये के लगभग 97.5 प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए थे, और केवल 8,897 करोड़ रुपये मूल्य के ऐसे नोट अब भी जनता के पास हैं. 19 मई, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर चलन में 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था.

2,000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने की दी गई सुविधा

ऐसे में दो हजार के नोट रखने वाली जनता और इकाइयों को शुरू में 30 सितंबर, 2023 तक इन्हें बदलने या बैंक खातों में जमा करने के लिए कहा गया था। बाद में इस समयसीमा को सात अक्टूबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया था। आठ अक्टूबर, 2023 से लोगों को आरबीआई के 19 कार्यालयों में नोट बदलने या उनके बैंक खातों में उतनी ही राशि जमा करने का विकल्प प्रदान किया गया है।

फोनपे ने किया इंडस ऐपस्टोर का जोरदार लॉन्चः भारतीय डिजिटल यात्रा में होगा एक गेम चेंजर

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

इप्दहाझ ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अपने Indus Appstore को उपभोक्ता के लिए लॉन्च की घोषणा की। Indus Appstore भारत के लिए एक अधिक प्रतिस्पर्धी और स्थानीयकृत मोबाइल ऐप स्टोर इकॉनमी बनाने का इप्दहाझ का प्रयास है, जो पहले से ही वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा मोबाइल ऐप डाउनलोड बाजार है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्टार्टअप संस्थापकों और टेक उद्योग के लीडरों ने भाग लिया, जो भारत के फलता-फूलता डिजिटल इकोसिस्टम के लिए इस लॉन्च के महत्व को दर्शाता है। Indus Appstore भारतीय उपभोक्ताओं को 45 श्रेणियों में 2 लाख से अधिक मोबाइल ऐप और गेम डाउनलोड करने की अनुमति देता है। यूजर इन ऐप्स को 12 भारतीय भाषाओं में आसानी से खोज पाएंगे, जिससे 95ङ्ग भारतीयों की भाषा से जुड़ी प्राथमिकता पूरी होंगी। उपभोक्ताओं के लिए नई ऐप खोज को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए ऐप स्टोर एक बिल्कुल नया शार्ट-वीडियो आधारित खोज की सुविधा भी प्रदान करता है।

कंप्रेस्ड बायो गैस सैक्टर में रिलायंस की बड़ी तैयारी

दो साल में 5,000 करोड़ रुपये का होगा निवेश

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड Reliance Industries Ltd (RIL) कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) में भी बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है। खबर है कि कंपनी अगले दो वर्षों में ?5,000 करोड़ से अधिक की लागत से 50 से अधिक सीबीजी संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल अगस्त में आरआईएल की वार्षिक आम बैठक में, अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने पांच वर्षों में 100 सीबीजी संयंत्र (CBG Plant) स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी। सीबीजी अपशिष्ट या बायोमास स्रोतों से उत्पादित ग्रीन फ्यूल है। इसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) के समान गुण हैं और इसका उपयोग ऑटोमोटिव, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए किया जा सकता है।

टेंडर जारी कर दिए गए हैं

रिलायंस के एक अधिकारी ने बताया कि आरआईएल ने 50 से अधिक सीबीजी प्लांट बनाने के लिए निविदा जारी की है। ये प्लांट अगले दो साल के अंदर लगने वाले हैं। इसके अलावा जल्द ही शेष प्लांट्स के लिए निविदा जारी करेगी। उन्होंने बताया कि यह टेंडर टेक्नोलोजी के साथ साथ इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए है। इस व्यक्ति ने बताया कि रिटेल से लेकर ऑयल रिफाइनिंग ग्रुप ने भी सीबीजी प्लांट की संख्या के लक्ष्य को 100 से संशोधित कर 106 कर दिया है। इस बारे में कंफर्मेशन के लिए ईटी ने आरआईएल को बीते 19 फरवरी को ही प्रतिक्रिया के लिए ईमेल भेजे गए थे, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया।

250 से 500 टन होगी क्षमता

रिलायंस के अधिकारियों ने बताया कि हर सीबीजी प्लांट की फीडस्टॉक प्रोसेसिंग क्षमता प्रतिदिन 250-500 टन होगी। इसमें सीबीजी प्रोडक्शन 10 टन से 20 टन प्रति दिन होगा। 10 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के प्लांट में अनुमानित निवेश लगभग 100 करोड़ रुपये है। आरआईएल की इन-हाउस टीम संयंत्रों के लिए फीडस्टॉक की सोर्सिंग करेगी। अधिकारियों का कहना है कि कंपनी सीबीजी प्रोडक्शन के लिए गन्ने से रस निकालने के बाद बचा निष्पंदन अवशेष sugarcane press mud और फीडस्टॉक की सोर्सिंग के लिए कई चीनी मिलों के साथ भी चर्चा कर रही है।

क्या कहा था अंबानी ने

अंबानी ने पिछले साल कंपनी के एजीएम कहा था, 'भारत लगभग 230 मिलियन टन नॉन कैटल फीड बायोमास का उत्पादन करता है। इसका अधिकांश हिस्सा जलाया जाता है तो कि वायु प्रदूषण में योगदान देता है। एक वर्ष की छोटी अवधि के भीतर, हम अपनी स्वदेशी विकसित तकनीक के आधार पर भारत के सबसे बड़े जैव-ऊर्जा उत्पादक बन गए हैं।' आरआईएल ने पहले ही जामनगर में अपनी रिफाइनरी सुविधा में दो सीबीजी डेमो इकाइयां स्थापित कर ली हैं और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पहला वाणिज्यिक पैमाने का सीबीजी संयंत्र चालू कर दिया है।

क्या है आरआईएल का लक्ष्य

आरआईएल ने अपनी सीबीजी इकाइयों के माध्यम से 5.5 मिलियन टन कृषि-अवशेषों और जैविक कचरे का उपयोग करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने लगभग 2 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सालाना 2.5 मिलियन टन जैविक खाद का उत्पादन करने का भी लक्ष्य रखा है। ऐसा होता है तो आयातित लिक्विड नेचुरल गैस में प्रति वर्ष लगभग 0.7 मिलियन टन की कमी आएगी। ये सीबीजी यूनिट्स आरआईएल को शीघ्र ही जियो-बीपी के फ्यूल रिटेल शॉप पर सीबीजी और बायो-सीएनजी (बायोगैस का शुद्ध रूप) की खुदरा बिक्री बढ़ाने में मदद करेंगी। Jio-BP आउटलेट्स की स्थापना रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा की गई है, जो RIL और ब्रिटिश ऊर्जा प्रमुख BP Plc का संयुक्त उद्यम है।

भारत के शास्त्रीय नृत्य के जरिए फ्लाइट सेफ्टी की शिक्षा

एयर इंडिया ने किया है ऐसा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भरतनाट्यम, ओडिशी, कथकली, ओडिशी, कत्थक, घूमर, बिहू, गिद्दा। यदि इन सब की बात करें तो आप कहेंगे कि ये भारत के शास्त्रीय (Classical) और लोक नृत्य (Folk Dance) की विधा हैं। देश के अलग अलग इलाकों में ये नृत्य खूब लोकप्रिय हैं और उत्सव और त्योहार का हिस्सा का बनते हैं। लेकिन यदि हम कहें कि नृत्य की इन विधाओं के जरिए हवाई जहाज में सफर के दौरान सेफ्टी के तौर-तरीकों की शिक्षा भी दी जा सकती है तो आप कहेंगे कि ऐसा भी कहीं होता है? लेकिन इसे संभव कर दिखाया है खालिस भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया (Air India) ने।

तेजी से बदल रहा है एयर इंडिया

आपको तो पता ही होगा कि सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया बिक गई है। इसे टाटा ग्रुप (Tata Group) ने खरीदा है। इस एयरलाइन को टाटा ग्रुप के पास आए दो साल पूरे हो गए हैं। टाटा ग्रुप के पास आने के बाद एयर इंडिया में तेजी से बदलाव हो रहा है। चाहे आप स्टाफ के बिहेवियर की बात करें, फ्लाइट के अंदर दी जाने वाली सर्विस की बात करें, एयर होस्टेस के ड्रेस की बात करें या फिर उड़ान के दौरान परोसे जाने वाले व्यंजनों की बात करें। सबमें आमूल चूल बदलाव हो रहा है। अब एयर इंडिया ने इनफ्लाइट सेफ्टी वीडियो में भी बदलाव किया है।

सेफ्टी मुद्रा

एयर इंडिया ने शुक्रवार को एयरलाइन का एक नया इनफ्लाइट सेफ्टी वीडियो जारी किया। इसका नाम सेफ्टी मुद्रा Safety Mudras दिया गया है। इसमें भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के जरिए नृत्यांगना एयर पैसेंजर्स को सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देती नजर आती हैं। इस सेफ्टी वीडियो को McCann Worldgroup के प्रसून जोशी, शंकर महादेवन और भारतबाला ने मिल कर तैयार किया है। करीब साढ़े चार मिनट के इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाला व्यक्ति भारतीय संस्कृति की विविधता और गहराइयों तक पहुंच जाएगा।

नृत्य के जरिए फ्लाइट सेफ्टी की शिक्षा, एयर इंडिया ने बनाया अनूठा वीडियो

नृत्य की इन विधाओं को मिला है वीडियो में स्थान

एयर इंडिया के इस फ्लाइट सेफ्टी वीडियो में तमिलनाडु के भरतनाट्यम, ओडिशा के ओडिशी ध्रेग, असम के बिहू Bihu, केरल के कथकली Kathakali और मोहिनीअट्टम Mohiniyattam, राजस्थान के घूमर Ghoomar और पंजाब के लोक नृत्य गिद्दा के जरिए विमान के सुरक्षा नियमों को समझाया गया है। हर नृत्य के जरिये एक विशेष सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को समझाया गया है।

इंटरनेशनल फ्लाइट्स में वीडियो से समझाया जाता है

आपने यदि कभी अच्छे एयरलाइन की इंटरनेशनल फ्लाइट्स में सफर की होगी तो आपको इसका अंदाजा होगा। दरअसल, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आमतौर पर लंबी दूरी की होती हैं। इनमें पैसेंजर्स के मनोरंजन के लिए टीवी स्क्रीन की व्यवस्था होती है। बिजनेस या फर्स्ट क्लास में तो सीटों के सामने टीवी स्क्रीन होता है। इकोनॉमी क्लास में हर सीट के पीछे एक मिनी टीवी की व्यवस्था होती है। ऐसी फ्लाइट्स में सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देने के लिए एयर होस्टेस नहीं आते बल्कि सेफ्टी इंस्ट्रक्शन वीडियो चला दिए जाते हैं।

10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनेगा भारत, जानिए कब तक हासिल होगा यह टारगेट

नई दिल्ली। एजेंसी

वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम (WEF) के प्रेजिडेंट बोर्गे ब्रेंडे (Borge Brende) ने कहा है कि भारत 10 ट्रिलियन इकॉनमी बनने की राह पर चल रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत अभी दुनिया की पांचवीं बड़ी इकॉनमी है। अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद भारत का नंबर है। भारत के 2026 में जापान और 2027 में जर्मनी से आगे निकलने की उम्मीद है। लेकिन भारत की इकॉनमी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे माना जा रहा है कि भारत इसी साल जापान को पीछे छोड़ देगा। ब्रेंडे ने कहा कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का दावोस में हमेशा बहुत-बहुत स्वागत है। भारत महत्वपूर्ण सुधारों से गुजरा है और आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनयिक परिदृश्य पर भारत की बड़ी छाप दिखेगी। WEF समय आने पर वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम इंडिया शिखर सम्मेलन के साथ भारत में वापस आने की उम्मीद करता है। ब्रेंडे ने कहा कि भारत सात फीसदी की दर से आर्थिक विकास कर रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा, 'भारत महत्वपूर्ण सुधारों से गुजरा है और ये दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन की तुलना में अच्छी स्थिति में है। भारत में विदेशी निवेश में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ रही है जो पहले दूसरे देशों में देखने को मिलता था।'

कब तक हासिल होगा लक्ष्य

WEF के प्रेजिडेंट ने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में 10 लाख करोड़ डॉलर की इकॉनमी बनने की राह पर है। देश में एफडीआई में काफी तेजी आ रही है। अब भारत में बहुत सारी विनिर्माण गतिविधियां हो रही हैं, जो अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में होती थीं। मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में कई मजबूत सुधार किया है। ऐसे में बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। जेफरीज इक्विटी रिसर्च के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी अगले चार साल में 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी। इसके बाद 2030 तक भारत की जीडीपी का आकार 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा।

भानु सप्तमी के दिन इस विधि से करें सूर्य देव की पूजा

भानु सप्तमी हर महीने कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को आती है। फाल्गुन महीने में 3 मार्च को भानु सप्तमी मनाई जाएगी। सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी और अचल सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है। भानु सप्तमी हर महीने कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को आती है । फाल्गुन महीने में 3 मार्च को भानु सप्तमी मनाई जाएगी। सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी और अचला सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यवसाय में लाभ मिलता है। घर में सकारात्मक माहौल होता है। इस आर्टिकल में भानु सप्तमी की पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताते हैं।

परिवार में आएंगी खुशियां

भानु सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पीले वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं। मंदिर को पानी से साफ कर दें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। उसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इस दौरान इस मंत्र का जाप करना न भूलें। - एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगत्पते। अनुकम्पय मां देवी गृहाणाघ्यं दिवाकर ।।

ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ? जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि काले तिल भी प्रवाहित करें। सूर्य देव को उसके बाद पीले रंग का फूल और जौ चढ़ा दें। फिर दीपक के साथ उनकी आरती करें। इस दौरान पूरी आस्था के साथ सूर्य चालीसा व सूर्य कवच को पढ़ें, जिससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। सूर्य देव को अंत में भोग लगाना न भूलें ।

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को अर्पित करें ये चीजें, प्राप्त होगी भोलेनाथ की कृपा

इस वर्ष महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024, शुक्रवार को मनाई जाने वाली है। इस तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में शिवरात्रि के दिन महादेव और माता गौरी की पूजा करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। ऐसे में शिवरात्रि पूजा के दौरान शिवलिंग पर कुछ चीजें जरूर अर्पित करनी चाहिए।

गंगा जल से करें अभिषेक

महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाया जाए, तो व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। इतना ही नहीं, जीवन में चल रहे कष्टों से छुटकारा मिलता है।

शिवलिंग पर अर्पित करें शहद

माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने या इसे अर्पित करने से व्यक्ति को आर्थिक लाभ हो सकता है। वहीं, यह भी मान्यता है कि शिवरात्रि के खास अवसर पर शिवलिंग पर घी अर्पित किया जाए, तो वंश में वृद्धि होती है।

सरसों का तेल चढ़ाएं

महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करना लाभदायी माना जाता है। इस प्रकार व्यक्ति ग्रह दोषों से मुक्त हो सकता है। इसके अलावा शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करने से व्यक्ति के लंबे समय से रुके हुए काम भी पूरे होने लगते हैं।

अर्पित करें बेलपत्र

भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र को आवश्यक माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से व्यक्ति को सुख-समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं, भगवान शिव को शमी के पत्ते, बेला के फूल और हरसिंगार के फूल चढ़ाए जाएं, तो हर मनोकामना पूरी होती है।

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

मार्च में इस दिन रखा जाएगा प्रदोष व्रत, जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

प्रदोष व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। मान्यता के अनुसार, ऐसा करने से लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। आइए, जानते हैं कि मार्च 2024 में कब रखा जाएगा प्रदोष व्रत।

मार्च माह का पहला प्रदोष व्रत

फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 मार्च को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि 8 मार्च को दोपहर 1 बजकर 19 मिनट से शुरू होगी। यह रात 9 बजकर 57 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में प्रदोष व्रत 8 मार्च को रखा जाएगा।

मार्च माह का दूसरा प्रदोष व्रत

प्रदोष व्रत के दिन रात्रि में भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा है। पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 मार्च को सुबह 4 बजकर 44 मिनट पर शुरू होगी। यह अगले दिन 23 मार्च को सुबह 7.17 बजे समाप्त होगी। ऐसे में प्रदोष व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा।

प्रदोष व्रत पूजा विधि

प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें। मंदिर की साफ-सफाई करें और एक दीपक जलाएं। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय करने की परंपरा है। इस दौरान भगवान भोलेनाथ का गंगाजल से अभिषेक करें। इसके बाद धतूरा, शमी के फूल और बिल्व पत्र आदि चीजें शिव जी को चढ़ाएं। अंत में आरती करें और शिव चालीसा का पाठ करें।

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ इंदौर (म.प्र.)

घर से नहीं हटाई ये चीज तो राहु-केतु बना देंगे कंगाल!

जानें मकान में बार-बार जाले लगने का मतलब

श्रीमती नीतू मित्तल
8959760040
ज्योतिषाचार्य, इंदौर (म.प्र.)

बहुत से घरों में मकड़ी के जाले लगे रहते हैं. लोग अक्सर इन्हें साफ भी करते हैं पर मकान में कुछ जगह ऐसी होती हैं, जहां लोगों को जाना रोज नहीं होता और वहां ये जाले लंबे समय तक बने रहते हैं. क्या आपको पता है कि ये जाले राहु-केतु का घर हैं और घर में बार-बार जाले लगने का मतलब क्या होता है? माना गया है कि जाला जितना पुराना होता है, वहां दरिद्रता का वास होता जाता है.

वास्तु शास्त्र में घर में मकड़ी के जाले अशुभ माने गए हैं. हम घर मे सफ़ाई तो करते हैं, पर कई बार मकड़ी के जाले नहीं हटाते. मकड़ी के जालों से घर में कंगाली आती है. कई घरों में बार-बार सफाई करने के बाद भी जाले लग जाते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, मकड़ी के जाले घर में लगना सही नहीं होता. जाले लगने से घर में भूत-प्रेत एवं बुरी शक्तियां तेजी से आकर्षित होती हैं. ये जाले राजा को रंक बनाने में देर नहीं लगाते.

मकड़ी के जाले में निवास बनाते हैं राहू केतु

हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जो लोग घर में सफाई नहीं रखते हैं, उनके घर में मकड़ी के जालों में राहु-केतु अपना निवास बना लेते हैं. राहु-केतु व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं. इसके कारण व्यक्ति मोह-माया में फंसता चला जाता है. फिर व्यक्ति के घर में दुर्घटनाएं, भयानक हादसे, भूत-प्रेत, बुरी आत्माएं अपना वास बना लेती हैं. घर में द्वंद बढ़ने से परिवार में झगड़े बढ़ने लगते हैं. नौकरी-व्यापार चौपट होने लगता है. कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है. बीमारियां घर को घेर लेती हैं.

राहु-केतु करोड़पति से कंगाल बना देते

घर में आपके गंदगी का माहौल होने पर राहु-केतु की दृष्टि अच्छी नहीं होती है. राहु-केतु की दृष्टि करोड़पति से कंगाल बना सकती है. घर में लगे मकड़ी के जाले मनहूसियत को दर्शाते हैं. घर में जाले लगे हो तो माता महालक्ष्मी भी साथ छोड़ देती हैं. अगर घर में थोड़े से भी जाले दिखें तो तुरंत उन्हें साफ कर देना चाहिए.

संपन्न लोगों का घर होता है ऐसा

आपने देखा होगा कि संपन्न लोगों के घरों में मकड़ी के जाले का नामोनिशान तक नहीं दिखता. उनके संपन्न होने की वजह घर में साफ-सफाई ही होती है. शास्त्रों के अनुसार अगर घर की अच्छे से देखरेख करते हैं, तो उस घर मे राहु-केतु की अच्छी दृष्टि पड़ने से लोग पल भर में करोड़पति बन जाते हैं.

सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट, हो गया इतना सस्ता, भाव देखकर हो जाएंगे खुश

नई दिल्ली। एजेंसी

सोने की कीमतों में एक बार फिर से भारी गिरावट आई है। आज सोना एमसीएक्स एक्सचेंज पर सुबह से ही गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। सोने के भाव गिरावट के बाद अब 62 हजार रुपये के करीब पहुंच चुके हैं। सोने की कीमत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। चांदी सस्ती हुई है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एक समय 63 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब चल रहे सोने के भाव अब लुढ़क गए हैं। गोल्ड की कीमतों में आने वाले समय में और गिरावट हो सकती है। पिछले दिनों सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये अच्छा मौका हो सकता है। हालांकि खरीदारी से पहले एक बार इसके लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लें।

क्या हैं गोल्ड के भाव

एमसीएक्स एक्सचेंज पर आज यानी बुधवार को 5 अप्रैल 2024 की डिलीवरी वाला सोना गिरावट के साथ 62,095 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। सोना आज सुबह 62,215 रुपये के भाव पर खुला था। वहीं 5 जून 2024 को डिलीवरी वाला सोना आज लुढ़कर 62,498 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है।

क्या है चांदी की कीमत

एमसीएक्स एक्सचेंज पर आज यानी बुधवार को 5 मार्च 2024 की डिलीवरी वाली चांदी गिरावट के साथ 68,798 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। वहीं 3 मई 2024 को डिलीवरी वाली चांदी लुढ़कर 70,588 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रही है।

सोने के वैश्विक भाव

बुधवार को सोने की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक वायदा भाव 0.48 फीसदी या 9.90 डॉलर की गिरावट के साथ 2,034.20 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिख रहा है। वहीं, सोने का वैश्विक हाजिर भाव इस समय 2,026.70 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिख रहा है।

चांदी की वैश्विक कीमत

सोने के साथ ही चांदी के वैश्विक भाव में भी बुधवार को गिरावट देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वायदा भाव 0.28 फीसदी या 1.24 डॉलर की गिरावट के साथ 22.48 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, चांदी का वैश्विक हाजिर भाव गिरावट के साथ 22.32 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

बीते दिनों बढ़े थे दाम

सोने और चांदी की कीमतों में बीते दिनों तेजी देखने को मिली थी। सोने की कीमत 62 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा चल रही थी। वहीं अब यह गिरावट के साथ 61 हजार रुपये के करीब पहुंच चुकी है। अब इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है।

6g Services:

नोकिया ने भारतीय विज्ञान संस्थान से मिलाया हाथ

6जी पर साथ मिलकर करेंगे काम

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में अब 6जी को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से यह मैसेज दिया था कि भारत अब 6G इंटरनेट कनेक्टिविटी की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के 6जी में अग्रणी भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाने वाली नोकिया (Nokia) ने आज यानी शुक्रवार को भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC) के साथ साझेदारी की घोषणा की है। नोकिया ने यह साझेदारी संयुक्त रूप से 6जी टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च करने के लिए की है। नोकिया और आईआईएससी बेंगलुरु में कंपनी की नई 6जी लैब में एक साथ काम करेंगे। यहां पर वह रिसर्च के तीन मुख्य सेक्टर जिसमें 6जी रेडियो टेक्नोलॉजीज, 6जी आर्किटेक्चर और 6जी एयर इंटरफेस में मशीन लर्निंग के इस्तेमाल को आगे बढ़ाएंगे।

नोकिया ने कही ये बात

नोकिया ने एक बयान में कहा कि यह सहयोग 6जी टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड इकोसिस्टम में अपनी ज्वाइंट रिसर्च में योगदान देने के उद्देश्य से आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क और एल्गोरिदम विकसित करेगा। नोकिया के मुख्य रणनीति और प्रौद्योगिकी अधिकारी निशांत बत्रा ने कहा, 'वैश्विक दूरसंचार मंच पर भारत का महत्व सबसे अधिक है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विज्ञान और शिक्षा जगत के सबसे प्रतिभाशाली बुद्धिजीवियों के साथ काम करने पर गर्व है क्योंकि 6जी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

नोकिया और आईआईएससी 6जी उपयोग के मामलों पर विशेष ध्यान देंगे जो भारत के लिए विशेष महत्व के क्षेत्रों को संबोधित करते हैं। इसे इस्तेमाल करने के मामलों में ज्यादा टिकाऊ और एनर्जी एफिसिएंट कम्यूनिकेशन सिस्टम बनाना, क्रिटिकल कम्यूनिकेशन के लिए नेटवर्क के लचीलापन और विश्वसनीयता में सुधार करना और एआई का यूज करने के साथ परिवहन सुरक्षा में सुधार, स्वास्थ्य देखभाल में वृद्धि और शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए 'सेंसर के रूप में नेटवर्क' टेक्नोलॉजीज का विकास करना शामिल है।

भारत के मिशन में योगदान करने का मौका

आईआईएससी के निदेशक प्रोफेसर गोविंदन रंगराजन ने कहा, 'आईआईएससी को 2030 तक 6जी टेक्नोलॉजी के लिए डिजाइन और डेवलेपमेंट में लीडिंग कंट्रीब्यूटर बनने के भारत के मिशन में योगदान करने का सौभाग्य मिला है, जैसा कि पीएम मोदी द्वारा जारी भारत 6जी विजन दस्तावेज़ में कल्पना की गई है।' पीएम मोदी ने पिछले साल मार्च में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में नए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू) एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने 'भारत 6जी विजन डॉक्यूमेंट' का भी अनावरण किया और देश में 6जी आरएंडडी टेस्ट बेड लॉन्च किया।

इन देशों की तरक्की में भारतीयों का बड़ा हाथ

नाम जानकर रह जाएंगे दंग

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। दुनिया के कई बड़े देश मंदी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत की इकॉनमी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। आईएमएफ के मुताबिक, साल 2026 में भारत जापान को भी पीछे छोड़ देगा। वहीं साल 2027 में वह जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। जिस तरह से अभी जापान और जर्मनी की इकॉनमी जिस तरह संघर्ष कर रही हैं, उससे लग रहा है कि भारत को टॉप तीन में पहुंचने में इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले साल भारत की इकॉनमी बड़े देशों में सबसे तेजी से बढ़ी थी और अगले दो साल भी यही स्थिति रहने का अनुमान है।

भारत में युवाओं की एक बड़ी आबादी है और माना जा रहा है कि उसे अगले कई साल तक डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा मिलता रहेगा। यानी अगला दशक भारत का होने जा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी की दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनकी तरक्की में भारतीयों (Indian Workers) का बड़ा हाथ है। भारतीयों की बदौलत दुनिया के कई देश तरक्की कर रहे हैं। आईए आपको बताते हैं इन देशों के बारे में।

कई देशों में काम कर रहे भारतीय

मौजूदा समय में भारतीय बड़ी संख्या में दुनिया के कई देशों में काम कर रहे हैं। भारत के सबसे ज्यादा वर्कर्स (Indian Workers) मध्य पूर्व के कई देशों में काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से बीते दिनों ऐसे देशों की लिस्ट जारी की गई थी, जहां पर भारतीय वर्कर्स की संख्या काफी ज्यादा है। ये ऐसे देश हैं जहां पर काम करने वाले ज्यादातर वर्कर्स भारतीय हैं। इन देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर यूएई का नाम आता है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 35.54 लाख भारतीय वर्कर्स काम करते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम सऊदी अरब का है। सऊदी अरब में करीब 22.19 लाख भारतीय वर्कर्स काम कर रहे हैं। पिछले दिनों इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है।

लाखों भारतीय कर रहे काम

दुनिया के ऐसे देश जहां पर भारतीय वर्कर्स बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं, उनमें कुवैत भी शामिल है। कुवैत में 8.29 लाख भारतीय वर्कर्स काम कर रहे हैं। कुवैत की तरह कतर में भी 8 लाख भारतीय वर्कर्स काम कर रहे हैं। ओमान का नाम भी इन्हीं देशों की लिस्ट में शामिल है। ओमान में 5.30 लाख भारतीय वर्कर्स काम कर रहे हैं।

टाटा मोटर्स और बंधन बैंक में वाणिज्यिक वाहनों के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

टाटा मोटर्स, वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी, ने देश के तेजी से बढ़ रहे निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके तहत टाटा मोटर्स के वाणिज्यिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को उनकी जरूरतों के मुताबिक फाइनेंसिंग के आसान समाधान मिलेंगे। इस गठजोड़ के तहत बंधन बैंक सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिये फाइनेंस मुहैया करेगी। ग्राहकों को बैंक के विशाल नेटवर्क और आसान पुनर्भुगतान के लिये बनी खास योजनाओं का फायदा होगा।

इस भागीदारी पर अपनी बात रखते हुए, टाटा मोटर्स में ट्रक्स के वाइस प्रेसिडेंट एवं बिजनेस हेड श्री राजेश कौल ने कहा, 'इस एमओयू के माध्यम से बंधन बैंक के साथ अपनी भागीदारी की घोषणा करके हम खुश हैं। अपने ग्राहकों को फाइनेंसिंग के आसान समाधान प्रदान करने के लिये हमारी प्रतिबद्धता में यह एक बड़ा कदम है। यह भागीदारी सुलभ एवं सक्षम वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिये हमारी प्रतिबद्धता दिखाती है। हम अपने ग्राहकों को उनके व्यावसायिक लक्ष्य हासिल करने के लिये सशक्त करना चाहते हैं। बंधन बैंक के साथ मिलकर हम अपने वाणिज्यिक वाहनों के महत्वपूर्ण ग्राहकों को ज्यादा सुविधा एवं सहयोग देंगे।''

इस घोषणा पर बंधन बैंक में कंज्यूमर लेंडिंग और मॉर्गेजेज के हेड श्री संतोष नायर ने कहा, 'वाहनों की फाइनेंसिंग के लिए आसान समाधान प्रदान करने के लिये बंधन बैंक को टाटा मोटर्स के साथ भागीदारी करके खुशी हो रही है। यह गठजोड़ वाणिज्यिक वाहनों के ग्राहकों की तरह-तरह की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिये हमारा समर्पण दिखाता है। हमें विश्वास है कि इस गठजोड़ से हम अपनी पहुँच बढ़ा सकेंगे और फाइनेंसिंग के विशिष्ट रूप से निर्मित समाधान दे सकेंगे। इस प्रकार वाणिज्यिक वाहनों के सेगमेंट में व्यवसायों की तरक्की में सहयोग मिलेगा।''

इंदौर एक अद्भुत शहर; यहाँ शिक्षा, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में बेहतरीन संभावनाएं: शेख मंसूर बिन खलीफा अल-थानी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

इंदौर एक अद्भुत जगह है। यह शहर शिक्षा, कृषि और भोजन से संबंधित विनिर्माण में बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा, उद्यमिता और नवाचार कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस शहर को बढ़ावा देंगी। 'मुझे यहाँ के लोग पसंद आए; वे बहुत स्वागत कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने परिवार के साथ हूं' । यह बात कतर शाही परिवार के महामहिम शेख मंसूर बिन खलीफा अल-थानी ने शनिवार को यहां 19वें प्रेस्टीज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन के अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कही। अल-थानी ने कहा कि वह गुणवत्तापूर्ण प्रतिभा में विश्वास करते हैं। 'मैं हमेशा गुणवत्तापूर्ण प्रतिभा वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि यही भविष्य की अर्थव्यवस्था है।' भारत की प्रतिभाओं की सराहना करते हुए अल-थानी ने कहा, 'भारत प्रचुर प्रतिभा, महान लोगों और महान मूल्यों वाला एक महान देश है।' एक सवाल के जवाब में शेख मंसूर ने कहा कि वह भारत में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, खासकर कृषि, शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता में। उन्होंने कहा, 'मैं उद्यमियों को समर्थन देने और उन्हें वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए स्टार्टअप समुदाय का समर्थन करना चाहूंगा।' इंदौर में निवेश के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि वो यहाँ निवेश के सम्भावना की तलाश कर रहे हैं। अल-थानी जो एमबीके होल्डिंग्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं ने कहा कि उन्होंने अपने इस यात्रा के दौरान दोनों समूहों के बीच व्यापार और शैक्षणिक सहयोग को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए प्रेस्टीज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रीज के साथ कुछ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि वह लोगों, सहयोग और साझेदारी में विश्वास करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से, व्यापारिक गठबंधन की तलाश करते समय और स्थानीय उद्योगों में निवेश पर विचार करते समय उनके पास स्थानीय लोग होंगे। कतर शाही परिवार के सदस्य ने कहा कि वह समुदाय के भीतर मूल्य बनाने में विश्वास करते हैं।

वियाट्रिस को लगातार तीसरे वर्ष भारत में ग्रेट प्लेस टू वर्क की मान्यता मिली

असाधारण कार्य परिवेश और कर्मचारियों में संतुष्टि के लिए मिली मान्यता

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मायलन लेबोरेटरीज़ लिमिटेड (वियाट्रिस कम्पनी) को लगातार तीसरी बार भारत में ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन रू की विशिष्ट मान्यता मिली है। यह मान्यता एक ऐसे कार्य परिवेश को बढ़ावा देने के लिए वियाट्रिस की प्रतिबद्धता का सम्मान है, जिसमें सकारात्मकता, भागीदारी और सभी का समावेश हो। इस परिवेश में कर्मचारियों की खुशहाली और प्रोफेशन में तरक्की को खास अहमियत दी जाती है। यह मान्यता वियाट्रिस द्वारा कर्मचारियों को यह अहसास देने का भी प्रमाण है कि वे महत्वपूर्ण हैं, संगठन उनके साथ खड़ा है और उनकी बात सुनी जाएगी।

ग्रेट प्लेस टू वर्क कार्य परिवेश की संस्कृति का पूरी दुनिया में आधिकारिक जानकार है। कम्पनी 1992 से पूरी दुनिया के 100 मिलियन से अधिक कर्मचारियों का सर्वे कर चुकी है और इससे प्राप्त गहरी सूझबूझ से यह परिभाषित करती है कि किसी संगठन के ग्रेट प्लेस टू वर्क बनने का आधार है विश्वास। उनके कर्मचारी सर्वे प्लैटफॉर्म संगठन प्रमुखों को फीडबैक, रियल टाइम रिपोर्टिंग और सूझबूझ देकर कर्मचारियों के बारे में रणनीतिक महत्व का निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

वियाट्रिस को पांच कैटेगरियों विश्वसनीयता, सम्मान, निष्पक्षता, गौरव और सहयोग में आकलन करने वाले ग्रेट प्लेस टू वर्क नेशनल ट्रस्ट इंडेक्स कर्मचारी सर्वे के अनुसार 89% प्रतिभागियों ने यह बताया कि वियाट्रिस इंडिया ग्रेट प्लेस टू वर्क है!

ऑल-न्यू सैमसंग गैलेक्सी फिट3 के साथ अपनी सेहत का रखें पूरा ध्यान

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने आज अपने नए फिटनेस ट्रैकर गैलेक्सी फिट3 को लॉन्च किया। यह सैमसंग की उन्नत स्वास्थ्य-निगरानी तकनीक को सबके लिए सुलभ बनाता है, जो हर किसी को अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करने और एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। गैलेक्सी फिट3 सैमसंग का सबसे लेटेस्ट वियरेबल डिवाइस है और इसमें व्यापक डिस्प्ले के साथ एक एल्यूमीनियम बॉडी है, जो यूजर्स को अपने स्वास्थ्य और सेहत से संबंधित डेटा पर नजर रखने की सुविधा देती है, जिसमें रोजाना की कसरत से लेकर शांतिपूर्ण नींद तक की चौबीसों घंटों की निगरानी शामिल है। सैमसंग इंडिया के एमएक्स बिजनेस के सीनियर डायरेक्टर, आदित्य बब्बर ने कहा, 'सेहत के इस नए युग में यूजर अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिक व्यापक जानकारी चाहते हैं और सैमसंग यूजर्स को उनकी सेहत यात्रा में मदद करने के लिए उन्नत स्वास्थ्य निगरानी उपकरण मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है।' उन्होंने कहा, 'हमारे नए फिटनेस ट्रैकर के रूप में, गैलेक्सी फिट3 आसान संसाधन प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को जाहिर करता है जो रोजमर्रा की सेहत को प्रोत्साहित करते हुए हर किसी को अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित करता है।'

गैलेक्सी फिट3, अपने बिल्कुल नए डिजाइन के साथ, यूजर्स बेहतर तरीके से काम करने, अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से समझने और बेहतर कनेक्टेड अनुभवों का आनंद ले सकते हैं

न्यू वन UI 6.1 अपडेट की मदद से अन्य गैलेक्सी डिवाइसेज भी गैलेक्सी एआई का कर पाएंगे इस्तेमाल

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मोबाइल एआई के लोकतंत्रीकरण को और अधिक विस्तार देते हुए, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने नए वन यूआई 6.1 अपडेट के माध्यम से और अधिक गैलेक्सी डिवाइसेस पर भी गैलेक्सी एआई फीचर्स उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ये अपडेट गैलेक्सी ए23 सीरीज, ए23 FE, Z फोल्ड5, Z Flip5 और Tab ए9 सीरीज में उपलब्ध होंगे, जिसकी शुरुआत मार्च के अंत से होगी। हाल ही में लॉन्च की गई गैलेक्सी ए24 सीरीज की तरह, यह अपडेट एक हाइब्रिड अप्रोच के माध्यम से यूजर्स के मोबाइल एआई अनुभव को नई ऊंचाई पर ले जाता है, जो ऑन-डिवाइस और क्लाउड-आधारित एआई को साथ जोड़ता है।

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल ईएक्सपीरियंस बिजनेस के प्रेसिडेंट और प्रमुख टीएम रोह ने कहा, 'गैलेक्सी एआई के साथ हम न केवल मोबाइल एआई के एक नए युग की शुरुआत करना चाहते हैं, बल्कि एआई को और अधिक सुलभ बनाकर यूजर्स को सशक्त करेंगे।' 'यह तो केवल गैलेक्सी एआई की शुरुआत है, क्योंकि हम 2024 के भीतर 100 मिलियन से अधिक गैलेक्सी यूजर्स तक इस अनुभव को पहुंचाना चाहते हैं और साथ ही हम मोबाइल एआई की असीमित संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए नए तरीके अपनाते रहेंगे।'

चुनौतियों से परे कम्युनिकेशंस

अब और भी अधिक गैलेक्सी यूजर्स एआई-समर्थित मॉडलों पर उपलब्ध बेहतर कम्युनिकेशंस वाली गैलेक्सी एआई सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिसमें चैट असिस्ट का उपयोग करके मैसेज टोन को एडजस्ट करने और 13 विभिन्न भाषाओं में मैसेज का अनुवाद करने की क्षमता शामिल है। गैलेक्सी यूजर लाइव ट्रांसलेट के माध्यम से रियल टाइम में वॉयस और टेक्स्ट अनुवाद की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इंटरप्रेटर के साथ, यूजर अपनी यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों के साथ सहज बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि स्प्लिट-स्क्रीन सुविधा लाइव बातचीत के लिए टेक्स्ट अनुवाद की सुविधा भी मुहैया कराती है।

असीमित उत्पादकता

गैलेक्सी इकोसिस्टम में गैलेक्सी एआई को शामिल करने से यूजर को एआई-समर्थित मॉडल पर रोजाना के काम में सहज अनुभव मिलेगा, जिससे क्षमता में वृद्धि होती है। सर्कल टू सर्च विद गूगल के माध्यम से सर्च में सुधार किया गया है, जो तेज सर्कल-मोशन जेस्चर के साथ सहज सर्च रिजल्ट देता है। नोट असिस्ट जैसी सुविधाएं यूजर्स को फॉर्मेट बनाने, सारांश तैयार करने और नोट्स का अनुवाद करने की सेवा देता है, जबकि ब्राउजिंग असिस्ट व्यक्तियों को समाचार लेखों के व्यापक सारांश तैयार करने में मदद करता है। वहीं ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट मीटिंग रिकॉर्डिंग को आसानी से ट्रांसक्रिप्ट करते हुए सारांश और अनुवाद तैयार कर सकता है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।